



पीओके में क्यों भड़का विरोध प्रदर्शन... पेज 5

दैनिक

कारखाने का सफर



आपकी ये 4 आदतें घर में अलक्ष्मी के वास... पेज 7

वर्ष 6, अंक 157

भोपाल, बुधवार 17 दिसंबर, 2025

पौष कृष्ण शुक्ल पक्ष, त्रियोदशी, 2082

मूल्य 2 रुपए

यादव समाज शिक्षित, संगठित और स्वावलंबी समाज है : किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष नगर निगम, भोपाल



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

अखिल भारतीय यादव/अहिर समाज द्वारा सैनिकों के सम्मान में आयोजित एक दिवसीय सम्मान समारोह में मुख्यअतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष सम्मिलित होकर कार्यक्रम को किया संबोधित। नगर निगम अध्यक्ष का स्वागत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कप्तान यादव, करण सिंह, हीरालाल, रामराज यादव, शीशुपाल यादव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हरीश यादव, युवा कार्यकारिणी सदस्य प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानप्रकाश, हरीनारायण यादव, शिवनारायण, प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आशा यादव, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं समाज की प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व पाषंद कमलेश यादव सहित सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं समाजजनों द्वारा किया गया। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अपने उद्बोधन में भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए तीन मूल

मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का उल्लेख करते हुए कहा कि यही मंत्र समाज को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यादव समाज शिक्षित, संगठित एवं आत्मनिर्भर समाज है, जो निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह पूरे यादव समाज के लिए गौरव का विषय है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिभा किसी जाति या संपन्नता की मोहताज नहीं होती, बल्कि परिश्रम, संघर्ष और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि यादव समाज के अनेक युवक भारतीय सेना में सेवा देकर राष्ट्र और समाज का मान बढ़ा रहे हैं। अंत में नगर निगम अध्यक्ष ने सैनिकों के सम्मान हेतु इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और समाज से शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया।

हेम्टू इंटक के प्रयास से कस्तूरबा अस्पताल में एक नई डाइलिसिस मशीन आ गई

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

कस्तूरबा अस्पताल काफी दिनों से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मशीनों के अभाव में कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें एक समस्या डाइलिसिस यूनित में डाइलिसिस मशीन की भी थी। डाइलिसिस यूनित काफी दिनों से पुरानी 2 मशीन पर चल रहा था, जो कि काफी दिनों से खराब पड़ी हुई थी और टैक्निकली अपनी लाइफ भी पूरी कर चुकी थी। इससे यहाँ डाइलिसिस करवाने वाले मरीजों को परेशान होकर बाहर रेफर करवा कर डाइलिसिस के लिए जाना पड़ रहा था, इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हेम्टू इंटक काफी दिनों से संघर्ष भी कर रही

थी। हेम्टू इंटक के अध्यक्ष राजेश शुक्ला एवं पदाधिकारी के अथक प्रयास से अस्पताल में एक नई डाइलिसिस मशीन आ गई है और उस मशीन से बाहर जाने वाले मरीजों का वापस फिर से यहाँ डाइलिसिस शुरू हो गया है। इसके अलावा एक और मशीन भी आने वाली है, जो लगभग अप्रैल माह तक आ जायेगी। * इसके अलावा अस्पताल का डाइलिसिस यूनित काफी पुराना और जर्जर हो गया है। इसके लिए राजेश शुक्ला ने कस्तूरबा अस्पताल की सीएमएस डॉ प्रमिला सचदेव से बात की तो उन्होंने कहा है कि डाइलिसिस यूनित को नई बिल्डिंग में आईसीयू के पास शिफ्ट करने के लिए कह दिया है जो कि जल्द ही शिफ्ट हो जायेगा।



बीएचईएल भोपाल की प्रतिनिधि यूनियन एआईबीईयू (संबद्ध-निफ्टू) ने श्रम एवं रोजगार शिखर सम्मेलन-2025 में किया प्रतिनिधित्व

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

देश के अग्रणी 16 राष्ट्रीय श्रम संगठनों द्वारा आयोजित श्रम एवं रोजगार शिखर सम्मेलन-2025 का आयोजन कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (निफ्टू) द्वारा (कंसेंट) के बैनर तले किया गया, जिसमें डॉ. दीपक जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निफ्टू व संयोजक कांस्टेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन विपट जायसवाल द्वारा किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री – श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल, भारत सरकार। उपस्थिति रहे।

नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता सहित श्रम सुधारों के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं की सराहना की गई। इस शिखर सम्मेलन में भोपाल बी एच ई एल की प्रतिनिधि यूनियन एआईबीईयू, संबद्ध निफ्टू की ओर से मध्यप्रदेश निफ्टू के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण गिरी, निफ्टू के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सोनी, निफ्टू के राष्ट्रीय सचिव विशाल वाणी, एबू के अध्यक्ष सतेंद्र कुमार एवं कार्यालय मंत्री योगेश देवस्कर ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त बीएचईएल कॉर्पोरेट, नई दिल्ली से कार्यकारी अध्यक्ष बलवंत सिंह रावत, दीपक कुमार, गुरदीप सिंह एवं जगदीप सैनी तथा बीएचईएल हरिद्वार से कुमुद कुमार श्रीवास्तव, गगन कुमार वर्मा, योगेश सैनी, प्रदीप सैनी एवं पिंटू यादव ने सम्मेलन में सहभागिता करते



हुए संगठन का सशक्त प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन के दौरान श्रमिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामनारायण गिरी को केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीयों द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जो बीएचईएल भोपाल एवं एआईबीईयू के लिए



अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है। यह शिखर सम्मेलन श्रमिक हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल सिद्ध हुआ है, जिससे देश में श्रम सुधारों की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने का सकारात्मक संदेश गया। श्रमिक संगठनों की पिछले 70

वर्षों से लंबित मांगों का निराकरण इन चार श्रम कानूनों में किया गया जिस पर विशेष चर्चा हुई। सम्मेलन में उपस्थित मंत्री को देश में व्यापक रोजगार अवसरों के सृजन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करने तथा न्यूनतम मजदूरी से निरंतर “लिविंग वेज” के रूप में निर्धारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिक संगठनों से निरंतर संवाद स्थापित कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर भविष्य में भी श्रमिकों के हित में आवश्यक सुधार किए जाते रहेंगे। साथ ही महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सभी क्षेत्रों में समान रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में किए गए श्रम सुधारों को महिला सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम बताया गया।

प्रदेश का सबसे बड़ा भोजपाल महोत्सव मेला में सामान्य दिनों में भी उमड़ रही भारी भीड़

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रोजाना गुलजार हो रहा भेल दशहरा मैदान पर भोजपाल महोत्सव मेला का सांस्कृतिक मंच

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर चल रहा भोजपाल महोत्सव मेला इन दिनों अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ मेला देखने पहुंच रहे हैं। मेला का सांस्कृतिक मंच कलाकारों की प्रस्तुति से लगातार गुलजार हो रहा है। बॉलीवुड से लेकर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को ड्रीम म्यूजिकल बैंड द्वारा प्रस्तुति दी गई। शाम 7.30 बजे मुख्य अतिथि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि चनश्याम चंद्रवंशी विधायक काला पीपल, भाजपा नेता गिरीश शर्मा, मेला अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास वीरानी, महामंत्री हरीश कुमार राम, उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी, महेंद्र नामदेव, अखिलेश नगर सहित मेला टीम ने गणेश वंदना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री राजपूत और विधायक ने मेला अध्यक्ष सहित पूरी समिति को प्रदेश स्तरीय इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि भोजपाल महोत्सव मेला मंच पर देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। कलाकार अपनी गीत गजलों और मनमोहक नृत्यों से लोगों का मनोरंजन करा रहे हैं। बॉलीवुड के कई गायकों के साथ ही लोक गायकों और लोकनृत्यों की टोलियां अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं।



मेले में मिल रही विभिन्न वैरायटी : महामंत्री हरीश कुमार राम ने बताया कि मेले में हस्त निर्मित स्वदेशी मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के साथ ही बनारस की साड़ी, सहरनपुर का बुडन,

कश्मीर के ऊलन, भदोही का कारपेट, राजस्थान की मेलाभाइन क्रॉकरी, ग्वालियर की गजक की विभिन्न वैरायटी मिल रही है। 100 से ज्यादा खान-पान के स्टाल के साथ ही विभिन्न आयटमों की करीब 400 दुकानें हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को मेले में एह ही स्थान पर जरूरत की हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है।

मेला टीम के नायक, संभाल रहे व्यवस्था : मेला टीम के सदस्य मेले की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। इनमें विनय कुमार, मो. जाहिर खान, सुनील शाह, मधु भवनानी, केश कुमार, चंदन वर्मा, दीपक शर्मा, गोपाल शर्मा, भूपेंद्र सिंह, मो. रहान खान, दीपक बैरागी, देवेंद्र चौकसे, सुनील वैष्णव, गौरव जैन, संदीप सहित मेला समिति से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं।

बीएचईएल ऑफिसर्स क्लब परिसर में क्रिकेट मैच के आयोजन का शुभारंभ

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

बीएचईएल ऑफिसर्स क्लब परिसर में क्रिकेट मैच के आयोजन का शुभारंभ प्रदीप कुमार उपाध्याय, कार्यपालक निदेशक, बीएचईएल, भोपाल ने किया। यह कार्यक्रम ऑफिसर्स क्लब के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक (फोडर्स एवं टीसीबी-मैनुफैक्चरिंग, कर्मिशियल एंड मेनटेनेन्स) रूपेश तैलंग के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी महाप्रबंधकों की जीवन संगीयों ने उत्साहपूर्वक मैच में प्रतिभागिता की। अपने संबोधन में उपाध्याय ने कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए ऑफिसर्स क्लब टीम के समर्पित प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से संगठनात्मक बंधन और कर्मचारी कल्याण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बल मिलता है। मैच का उद्देश्य सौनियर लीडरशिप और उनके परिवारों के बीच सौहार्द बढ़ाना, आपसी संबंध को मजबूत करना और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन को बढ़ाना था।



दैनिक कारखाने का सफर अखबार का संपादकीय कार्यालय

गोविंद टॉवर, क्वालिटी रेस्टोरेंट के पास, एसबी स्टूडियो के ऊपर पिपलानी पेट्रोल पंप के पास, सोनागिरी चौराहा रायसेन रोड भेल भोपाल। मोबाइल नंबर: 9826035849, 9425006706



‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ की प्रदर्शनी से जागी राष्ट्रभक्ति की भावना

दिल्ली में ‘शिवकालीन शस्त्र संग्रहालय’ स्थापित करने का सांस्कृतिक मंत्री

का आश्वासन! छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों की उमंगपूर्ण सहभागिता



दैनिक कारखाने का सफर। नई दिल्ली

देश की राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित भव्य ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ के अंतर्गत ‘स्वराज्य का शौर्यनाद’ नामक प्रदर्शनी में राष्ट्रभक्ति, ईश्वरी कृपा और शौर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। भारत मंडपम के हाल नं. 12 में 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में शिवकालीन शस्त्रों का प्रदर्शन, वंदे मातरम प्रदर्शन, आध्यात्मिक वस्तुएँ तथा ग्रंथ प्रदर्शनी का आकर्षक दर्शन कराया गया।

इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों, अभिभावकों, हिंदुत्वनिष्ठ जनों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को न केवल शिवकालीन शस्त्रों को देखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें इतिहास के वीर पुरुषों द्वारा उपयोग किए गए शस्त्रों को प्रत्यक्ष स्पर्श करने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। इस दैवी अनुभव ने उपस्थित जनों के मन में स्वराज्यकालीन पराक्रम और शौर्य की अनुभूति को जीवंत किया।

इस अवसर पर दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में स्थायी ‘शिवकालीन शस्त्र संग्रहालय’ स्थापित किए जाने का आश्वासन दिया।

इस प्रदर्शनी का अवलोकन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय ललित, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य तथा भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्त सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा सहित अनेक संत-महंत, वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, संपादक, पुलिस अधिकारी, उद्योगपति, अधिवक्ता, सैन्य अधिकारी एवं हिंदू संगठनों के प्रमुखों ने बड़े उत्साह के साथ किया।

दिल्ली की अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने शस्त्रों की बनावट, विज्ञान और उनके उपयोग की जानकारी लेकर भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा प्राप्त की। इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक

सदुर चारुदत्त पिंगळे, सदुर नीलेश सिंगबाल और सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रकार्य में सक्रिय योगदान का आवाहन किया।

अध्यापिका सारिका शर्मा ने कहा, “विद्यार्थियों ने जब स्वयं इतिहासिक शस्त्रों को हाथ में लिया, तब उनमें राष्ट्रगौरव और आत्मसम्मान की भावना जागी।” विद्यार्थिनी पूजा कौशिक ने कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई के कार्यों से मुझे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिली।”

इयत्ता 7वीं की छात्रा आराध्या ने कहा, “मैं बड़ी होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह राष्ट्र के लिए कार्य करूंगी।”

इस प्रदर्शनी ने समाज में स्वाभिमान, शौर्य और सनातन संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को सुदृढ़ किया है। ‘शौर्य जागरण से राष्ट्र जागरण तक’ के उद्देश्य से आयोजित यह प्रदर्शनी दिल्ली के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रेरणादायी उपक्रम सिद्ध हुई।

होम से जीएडी को पहुंचा पुलिस भर्ती बोर्ड प्रपोजल,

15 अगस्त को सीएम ने किया था ऐलान



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के करीब चार माह बाद गृह विभाग ने प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को भेजा है। इसके बाद अब वित्त और विधि विभाग के परीक्षण के बाद इस मामले को कैबिनेट में लाए जाने की कवायद होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 अगस्त को पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। पुलिस भर्ती बोर्ड का प्रस्ताव दक्षिण के राज्यों के साथ यूपी और गुजरात के भर्ती बोर्ड की स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर लंबे समय से चल रही कवायद में तब तेजी आने के संकेत मिले थे जब मुख्यमंत्री डॉ यादव ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर सीएम निवास में हुए कार्यक्रम में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। इसके पहले यह प्रस्ताव पीएचक्यू में तैयार होकर रोक दिया गया था क्योंकि तब प्रशासनिक तौर पर इसे मंजूरी मिलने के संकेत नहीं मिले थे लेकिन जब सीएम ने घोषणा की तो इसके लिए बंद फाइल को फिर नए सिरे से खोलकर प्रस्ताव तैयार किया गया। बताया जाता है कि इस प्रस्ताव पर 100 दिन के विचार मंथन के बाद गृह विभाग ने अब इसे जीएडी को भेजा है। इसमें भर्ती बोर्ड के संरचनात्मक प्रक्रिया और उसके कार्य दायित्व की जानकारी दी गई है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर जीएडी विधि विभाग और वित्त विभाग से भी सुझाव ले सकता है क्योंकि आमतौर पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद भर्ती बोर्ड के गठन

का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2012 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान पुलिस कॉन्स्टेबल और उप निरीक्षक भर्ती की प्रणाली में बदलाव किया गया था। इसके पहले पुलिस मुख्यालय की भर्ती एवं चयन शाखा के अंतर्गत हर जिले में समिति गठित की जाती थी। इसमें सबसे पहले शारीरिक परीक्षा होती थी, जिसमें से लगभग 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चुना जाता था। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। इन तीनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग समितियां गठित की जाती थीं। बाद में सरकार ने लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी व्यापम (अब कर्मचारी चयन मंडल) को सौंप दी। पीएचक्यू अफसरों के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन के मामले में एमपी से आगे दक्षिण भारत के राज्य हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कई दशकों से पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी पहले ही पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इन पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से अब तक लाखों पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की घोषणा से एक वर्ष पहले ही पुलिस मुख्यालय ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी थीं। पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए श्यामला हिल्स क्षेत्र में मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य जारी है। इस भवन का निर्माण पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

800 संगठनों का संकल्प- सनातन संस्कृति की रक्षा का!

‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ के

समापन में शौर्य और संस्कृति की प्रेरणा!

दैनिक कारखाने का सफर। नई दिल्ली

देश की राजधानी स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुए दो दिवसीय ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ में देशभर से तीन हजार से अधिक हिंदू भक्तों और 800 से अधिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर संत-महंत, मंत्री, उद्योजक, अधिवक्ता, चिंतक और रक्षा विशेषज्ञों ने सनातन राष्ट्र की स्थापना हेतु संस्कृति के संरक्षण का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। ‘सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य’ विषय पर हुए मार्गदर्शन तथा शस्त्र-प्रदर्शन से उपस्थित जनसमूह में अदम्य शौर्य और प्रेरणा का संचार हुआ।

“भारत बनेगा प्रजासत्ताक हिंदू राष्ट्र” – स्वामी विज्ञानानंद जी

महोत्सव के समापन अवसर पर आयोजित ‘सनातन राष्ट्र संकल्प संत सभा’ में ‘हिंदुओं का सांस्कृतिक घोषणा पत्र’ विषय पर बोलते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद जी ने कहा कि जो राष्ट्र हिंदू जीवन-पद्धति अपनाएगा, वही सच्चे अर्थों में हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वतंत्रता-पूर्व भारत समृद्ध था । सूर्य के उदय से अस्त तक का भूभाग हिंदू अधिपत्य में था। आज हिंदुओं की सत्ता केवल भारत के कुछ राज्यों तक सीमित है। अतः केवल त्योहारों में रमने के बजाय, शेष प्रदेशों को

पुनः हिंदू संस्कृति के रंग में लाना प्रत्येक का कर्तव्य है। तभी भारत केवल हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि “प्रजासत्ताक हिंदू राष्ट्र” बनेगा।

“चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा नीति बने” – पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी

केवल चरित्रवान लोग ही धर्मयुद्ध कर सकते हैं। जिनके पास चरित्र नहीं होता, वे युद्ध नहीं जीत सकते। भारत के पास चरित्र होने के कारण पाकिस्तान के विरुद्ध हुए अनेक छोटे-बड़े युद्धों में भारत को सफलता मिली। चरित्र निर्माण करना आसान नहीं है और चरित्र का शिक्षा से सीधा संबंध नहीं होता। अनेक उच्च शिक्षित लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। वर्तमान शिक्षा युवाओं में चरित्र निर्माण करने में असमर्थ है, इसलिए केंद्र सरकार को चरित्र निर्माण करने वाली शैक्षणिक नीति तैयार करनी चाहिए,

ऐसा आवाहन ‘पावन चिंतनधारा आश्रम’ के संस्थापक पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी ने किया।

“संविधान में यह भेदभाव क्यों?” – रमेश शिंदे

हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सेक्युलर देश’ कहा गया है, किंतु धारा 25 से धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रावधान और नियम बनाए गए हैं । यह समानता के सिद्धांत के विपरीत है। सच में यदि देश सेक्युलर है तो फिर यह भेदभाव क्यों?

छत्तीसगढ़ के शदापीठ दरबार के पीठाधीश्वर प.पू. युधिष्ठिरलाल महाराज ने आह्वान किया कि उपस्थित सभी व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में सनातन राष्ट्र स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाएं। हिंदू जनजागृति समिति के धर्मप्रचारक सदुर नीलेश सिंगबाल ने कहा कि भावान ने गीता में कहा है, “न मे भक्तः प्रणश्यति” अर्थात “मेरे भक्त का नाश नहीं होता।”

इसलिए संकट के समय में सुरक्षा के साथ ईश्व रभक्ति का मार्ग ही कल्याणकारी है। महोत्सव का समापन ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुआ। इस महोत्सव के आयोजन के लिए भारत सरकार के कला व संस्कृति विभाग, भाषा विभाग, सांस्कृतिक मंत्रालय तथा दिल्ली पर्यटन विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ।

‘किस-किस को प्यार करूं-2’ में प्रिंसिपल बनी भोपाल की रश्मि, कहा-

कपिल शर्मा बोले प्रिंसिपल मैम के रोल के लिए आप परफेक्ट हैं

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

अब्बास-मस्तान निर्देशित फिल्म ‘किस-किस को प्यार करूं 2’ रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कपिल शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। भोपाल की गमंच कलाकार और शिक्षिका रश्मि गोल्या का कहना है कि यह फिल्म पूरी तरह से हेल्टी और फैमिली कॉमेडी है। पार्ट-वन जहां दर्शकों को खूब हंसाने में कामयाब रहा था, वहीं पार्ट-टू उससे भी ज्यादा कॉमिक और मनोरंजक है। रश्मि ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कपिल शर्मा और उनकी टीम के साथ काम करने का अनुभव रश्मि के लिए बेहद खास रहा। शूटिंग के दौरान बातचीत में कपिल शर्मा ने खुद कहा कि प्रिंसिपल मैम के रोल के लिए उनका सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। रश्मि

गोल्या फिल्म में स्कूल की प्रिंसिपल की भूमिका निभा रही हैं। वह बताती हैं कि उनका रोल इंटरवल के बाद शुरू होता है और स्कूल से जुड़े सीन कहानी में नया मोड़ लाते हैं। इन सीन्स में कई ऐसे मौके हैं, जहां सच्चाई सामने आते-आते रह जाती है।

प्रिंसिपल के किरदार में डायलॉग्स और रिएक्शंस दर्शकों को खूब पसंद आएंगे। रश्मि कहती हैं कि जब भोपाल में शूटिंग होती है और यहां के थिएटर कलाकारों को ऑडिशन का मौका मिलता है, तो यह शहर के कलाकारों के कला व संस्कृति बात होती है। उन्होंने भी इसी प्रक्रिया के तहत ऑडिशन दिया। कई राउंड की स्क्रीनिंग के बाद उनका चयन हुआ। उनके अनुसार, सालों तक थिएटर करने के बाद यह रोल मिलना उनकी मेहनत का नतीजा है।

बताती हैं कि वह असल जिंदगी में भी टीचिंग से जुड़ी हैं, इसलिए यह किरदार उनके रियल कैरेक्टर के बेहद करीब था और उसे निभाना उनके लिए स्वाभाविक हो गया। रश्मि

एमपी में फिर शीतलहर का दौर, 5 जिलों में अलर्ट, 22 जिलों में घना कोहरा

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ मध्यप्रदेश में फिर से कोल्ड वेव यानी, शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भोपाल, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर-सीहोर में कोल्ड वेव का अलर्ट है। वहीं, भोपाल, ग्वालियर समेत 22 जिलों में घना कोहरा छाएगा। कोहरे की वजह से ट्रेनें-प्लाइट भी डिले हो रही हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, सिंगरीली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और विदिशा में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। वहीं, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, मंडला, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर में भी कोहरा छाया रहेगा। कोहरा छाने के दौरान वाहनों को सावधानी से चलाने की समझाइश भी दी गई है। इससे पहले मंगलवार की सुबह छतरपुर के नौगांव में 500 से 1 हजार मीटर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, खजुराहो-मंडला में 1 से 2 किलोमीटर, इंदौर, राजगढ़, सागर, उज्जैन, जबलपुर-गुना में 2 से 4 किलोमीटर तक दृश्यता दर्ज की गई।

दिल्ली तरफ और उत्तर भारत में घने कोहरे और खराब मौसम का असर लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी रेल यातायात पर देखने मिला। दिल्ली की ओर से भोपाल आने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंचीं। सबसे

ज्यादा असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा, जिनमें कुछ ट्रेनें 6 से 7 घंटे तक लेट रहीं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेल अधिकारियों के अनुसार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। हालांकि, ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगाए गए हैं, लेकिन उनका असर उतना कारगर नहीं हो पा रहा है, जितना अपेक्षित था। इसी वजह से ट्रेनों की गति कम रखनी पड़ रही है, जिससे देरी बढ़ रही है।

पचमढ़ी में मंगलवार सुबह तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानी इलाके हवाई पट्टी गोल्फ कोर्स झील इलाकों में ओस बर्फ की चादर की तरह जम गई। पचमढ़ी में मंगलवार सुबह तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानी इलाके हवाई पट्टी गोल्फ कोर्स झील इलाकों में ओस बर्फ की चादर की तरह जम गई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार-मंगलवार की रात प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड लुढ़क गया। भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात रही। यहां तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

साल 2016 से अब तक 10 साल में यह तीसरी सबसे सर्द रात रही। पिछले साल 16 दिसंबर को पारा 3.3 डिग्री दर्ज किया गया था। भोपाल देश का 8वां और मप्र का दूसरा सबसे ठंडा शहर बन रहा। प्रदेश में शाजापुर में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में तापमान 5.4 डिग्री, ग्वालियर-जबलपुर में 9 डिग्री और उज्जैन में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा, सतना और सीधी में विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक रही। शाजापुर सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 4.4 डिग्री पहुंच गया।

गतांग से आगे : लोक कल्याण हेतु दादाजी का अवतरण

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

आनंद, सानंद और परमानंद की परिकल्पना श्री श्री 1008 श्री दादाजी के दरबार में पूर्ण होती है, जहाँ मनुष्य की समस्त आशाएँ, आकांक्षाएँ और महत्वाकांक्षाएँ साकार हो जाती हैं तथा सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आस्था के आयाम बचपन से लेकर 15 जुलाई 1991 तक साईंखेड़ा में अपने निवास में ही रहे। साईंखेड़ा स्थित दादाजी पहले सिंगल स्टोरी का मकान था उसमें बाहर एक दहलान फिर अंदर एक कमरा और एक किचन इत्यादि था बीच के कमरे में बड़े दादा जी का स्थान था उसमें भी दो खंड थे ऊपर वाले खंड में भगवान शिव एवं अन्य देवी देवताओं की फोटो और शिवलिंग इत्यादि थे और नीचे का स्थान बड़े दादाजी का था साईंखेड़ा में भी दादाजी नियमित रूप से दोनो टाइम पूजन इत्यादि किया करते थे और पहले रोज जो भी श्रद्धालु आते थे तुरंत उनकी समस्या का समाधान बड़े दादा जी से पूछकर किया करते थे। एक दिन दादाजी जब अपनी पूजन समाप्त कर बड़े दादाजी से प्रार्थना कर रहे थे उसी समय साईं खेड़ा में एक मास्टर साहब त्रिपाठी जी दादाजी के पास पहुंचे तब दादाजी ने त्रिपाठी जी मास्टर साहब से कहा कि आप दो अगरबत्ती बड़े दादा जी के सामने लगाएं तब मास्टर साहब ने दो अगरबत्ती लगाकर बड़े भावुक भाव भगवान शिव का एक भजन गाने लगे और



इतने तल्लीनता से गाया कि उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे तभी दादाजी भी भावुक हो गए और उन्होंने बड़े दादा जी से प्रार्थना की और अचानक मास्टर साहब, सामने मंदिर की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगे और यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। तब दादाजी ने मास्टर साहब से पूछा कि क्या हुआ ? तब मास्टर साहब ने बताया कि बड़े दादाजी ने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझे दर्शन दिए हैं तब दादाजी ने देखा की बड़े दादाजी मंदिर के ऊपर वाले

खंड में खड़े होकर आशीर्वाद की मुद्रा में है। तब दादाजी ने मास्टर साहब से पूछा कि बड़े दादा जी कहां हैं, मास्टर साहब ने बोला कि ऊपर खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह दादा जी ने कई व्यक्तियों को बड़े दादाजी अर्थात भगवान भृंगी ऋषि के दर्शन करवाए। साईंखेड़ा में एक मास्टर साहब थे। वे पहले दादाजी के साईंखेड़ा वाले घर में स्थित मंदिर में या यूं कहें लगाने गए, अगरबत्ती लगाने के बाद बड़े



भावुक भाव से उन्होंने एक शिव स्तुति गाई । इस स्तुति के खत्म होते पूजन के स्थान पर सोमवार एवं गुरुवार को अगरबत्ती लगाने जाया करते थे। एक सोमवार जब वे अगरबत्ती होते उनकी दोनों आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और वे भाव विभोर होकर भगवान के मंदिर की तरफ देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा की दादाजी के मंदिर के ऊपर वाले स्थान पर बड़े दादाजी खड़े होकर आशीर्वाद की मुद्रा में उन्हें दर्शन दिए। वे जोर-जोर से के प्रेम भाव से अश्रु प्रवाहित

करने लगे। तब पूजा के स्थान पर बैठे दादाजी ने उनसे पूछा क्या दिखाई दे रहा है ? तब मास्टर साहब ने बताया कि ऊपर वाले स्थान पर बड़े दादाजी खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तब दादाजी ने देखा कि बड़े दादा जी वास्तव में ऊपर ही खड़े हैं। उस स्तुति की कुछ लाइनें इस प्रकार है- हे चंद्र मौली हे चंद्रशेखर, हे शंभू त्रिलोचन हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारी अर्चन। जय जय हे शंकर हे भस्मांग सुंदर हे पशुपति हरिहर ।।

मंदाकिनी से दानिश चैराहे तक की 80 फिट सड़क में 3 मीटर चौड़ाई तुरंत बढ़ाई जाए मात्र 3 वर्ष बाद ही किए गए टेंडर एवं अनुमति की जांच करवाने की कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने मांग की

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

निर्माण भवन भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश के प्रमुख अभियंता ENC से मुलाकात कर ज्ञापन दिया एवं लोक निर्माण विभाग भोपाल परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, मंडल क्रमांक 1, भोपाल के अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन की प्रतिलिपि देकर मंदाकिनी चौराहे से दानिश कुंज अग्रसेन चौराहे तक बन रही व्हाइट टॉपिंग सड़क को दोनों तरफ तुरंत 3 मीटर बढ़ाने एवं मात्र 2021 से 2022 में बनी सड़क को मात्र तीन वर्ष बाद ही पुर्ननिर्माण कर मध्यप्रदेश की पहली white topping सड़क का निर्माण कार्य करने एवं इसके टेंडर प्रक्रिया एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई अनुमति की उच्चस्तरीय जांच करवाकर कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने बताया कि कोलार के वार्ड 82 में मंदाकिनी चैराहे से लेकर जे के हॉस्पिटल होते हुए दानिश कुंज अग्रसेन चौराहे तक की 80 फीट पर White Topping सड़क का निर्माण कार्य जारी है, लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह द्वारा किए गए भूमिपूजन के समय यह सड़क राजधानी परियोजना संभाग क्रमांक 1, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा किया जाना था मगर अब इस सड़क को वर्तमान में लोक निर्माण विभाग भोपाल संभाग क्रमांक 2 द्वारा बनाया जा रहा है और सड़क निर्माण कार्य करते हुए दोनों तरफ मात्र 7 मीटर की सड़क निर्माण कर ही बनाई जा रही है जबकि पूर्व में रोड 10 मीटर की थी. इस सड़क के दोनों तरफ मात्र 7 मीटर के ही निर्माण से आमजनता को भारी असुविधा और दुघटना का अभी से सामना करना पड़ रहा है। मंदाकिनी चौराहे से दानिश कुंज चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ व्यापारियों एवं आम जनता को 3 मीटर और सड़क नहीं बनने से हो रही भारी परेशानी साफ दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के पी एस राणा से मांग की है कि मंदाकिनी चौराहे से दानिश चौराहे तक निमित व्हाइट टॉपिंग सड़क को दोनों तरफ तीन मीटर और निर्मित किया



जाए ताकि दोनों और 10-10 मीटर की सड़क बन जाए जिससे कि आम जनता और व्यापारियों को कोई भी असुविधा एवं परेशानी का सामना नहीं करना पड़े..आपसे विनम्र आग्रह है कि इस सड़क को दोनों और 3-3 मीटर बढ़ाने का कार्य लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा तुरंत किया जाए ताकि जल्द ही पूरी सड़क का निर्माण कार्य जनहित में पूर्ण हो और आमजनता को सुविधा मिले। जिला कांग्रेस कमिटी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने ईएनसी के पी एस राणा से द्वितीय मांग की है कि मंदाकिनी चौराहे से दानिश कुंज चौराहे तक बनने वाली मध्यप्रदेश की पहली व्हाइट टॉपिक सड़क का निर्माण कार्य 2021-2022 में निर्मित सीसी रोड के ऊपर ही 11 करोड़ में किया जा रहा है जबकि पूर्व में राजधानी परियोजना प्रशासन,CPA भोपाल द्वारा बनाई गई इस सड़क का निर्माण कार्य 2021 से 2022 में पूर्ण किया गया था और 10 वर्षों तक सड़क की गुणवत्ता की गारंटी आम जनता को दी गई थी मगर मात्र 3 वर्ष बाद ही 2025 की शुरुआत में लोक निर्माण विभाग राजधानी परियोजना संभाग क्रमांक 1 द्वारा 3 वर्ष पूर्व 2022 में ही करोड़ों में निर्मित हुई इस

सड़क का टेंडर क्यों निकाला गया, ये पूरी तरह जांच का विषय है। जब इस सड़क का निर्माण कर 2022 में मात्र 3 वर्ष पूर्व ही हुआ था तो लोक निर्माण विभाग द्वारा आखिर क्यों आम जनता के 11 करोड़ रुपए से वर्तमान में निर्मित की जा रही व्हाइट टॉपिंग सड़क को 2022 में बनी हुई सड़क के ऊपर ही बनाया गया जा रहा है, इससे तो 11 करोड़ रूपये का शासन का नुकसान हो रहा है क्योंकि करोड़ों रूपये खर्च करके यह सड़क मात्र कुछ वर्ष पूर्व ही बनाई गई थी। कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने ज्ञापन में मांग की है कि मंदाकिनी चौराहे से दानिश कुंज अग्रसेन चौराहे तक बनाई जा रही सड़क के इस वर्ष 2025 में निकाले गए टेंडर और टेंडर के कारणों की जांच की जाए एवं इस सड़क निर्माण की राजधानी परियोजना संभाग क्रमांक 1, लोक निर्माण विभाग,भोपाल द्वारा मात्र 3 वर्ष बाद ही दी गई सड़क निर्माण के लिए दी गई अनुमति की भी उच्चस्तरीय जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जावे।

कांग्रेस किसानों पर बहा रही मगरमच्छ के आंसू! सचिन यादव पर भाजपा प्रवक्ता डॉ दुर्गेश केसवानी का तीखा हमला

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश केसवानी ने पूर्व कृषि मंत्री एवं कांग्रेस विधायक सचिन यादव द्वारा मोहन सरकार को किसान विरोधी बताए जाने पर बेहद आक्रामक पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस और सचिन यादव पर तीखे शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को किसानों की चिंता नहीं है और वे केवल झूठ व भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन यादव किसानों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और मध्य प्रदेश का किसान यह अच्छी तरह जानता है कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों के साथ केवल धोखा, छल और कपट किया है। कांग्रेस ने हमेशा किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला है और जनता को गुमराह करने का काम किया है। भाजपा प्रवक्ता ने कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस एक भी ऐसा किसान सामने लाकर दिखाए, जिसका 2 लाख रुपए तक का कर्ज वास्तव में माफ किया गया हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी को सिर्फ चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया और सत्ता में आते ही अपने वादों से मुंह मोड़ लिया। डॉ. केसवानी ने तीखे लहजे में कहा कि कांग्रेस यह बात अच्छी तरह समझ ले कि झूठ



और भ्रम फैलाने से राजनीति नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने सच में किसानों की कर्ज माफी की होती, तो आज वह विपक्ष की बेंच पर बैठी नहीं होती। कांग्रेस की असलियत किसान पहचान चुका है और इसी कारण उसे बार-बार जनता ने नकारा है। उन्होंने कृषि विकास को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिन यादव अपने कार्यकाल की कृषि विकास दर और भाजपा सरकार के समय की कृषि विकास दर का खुद आंकलन कर लें। भाजपा सरकार के समय प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और

यही कारण है कि भाजपा छह बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कहा कि भाजपा सरकार सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के भविष्य को उज्जल बनाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि MSP के माध्यम से किसानों के हितों के लिए लगातार काम किया जा रहा है और भाजपा सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए शब्द-ज्ञान और विकास के मंत्र का अक्षरशः पालन कर रही है। सरकार का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संशक्तिकरण पर है और इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। गरीबों के कल्याण, युवाओं के भविष्य निर्माण और अन्नदाताओं के हितों की रक्षा को सरकार ने अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। नीतियां और योजनाएं इसी सोच के साथ लागू की जा रही हैं। अपने बयान के अंत में डॉ. केसवानी ने साफ शब्दों में कहा कि किसान पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी भाजपा के साथ है और आने वाले समय में भी भाजपा के साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितना भी झूठ फैलाने की कोशिश करे, किसान सच्चाई जानता है और भाजपा पर उसका भरोसा अडिग है।

कैबिनेट बैठक:3 जिलों में बनने वाले बांध प्रोजेक्टों में पुनर्वास के लिए 1782 करोड़ रुपए मंजूर

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में नर्मदा व उसकी सहायक नदी पर बनने वाली अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बांध प्रोजेक्ट में डूब प्रभावित 13,873 परिवारों के लिए राज्य सरकार ने 1,782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित सामान्य परिवारों को अब पुनर्वास के लिए 12.50 लाख रुपए और एससी-एसटी परिवारों को 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया। इन तीनों परियोजनाओं के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए डीपीआर में पहले से 1,656.2 करोड़ रुपए मंजूर हैं। 1,782 करोड़ का स्पेशल पैकेज इसके

अतिरिक्त मंजूर किया गया है। इस तरह पुनर्वास पर अब 3,438.2 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इन तीनों प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,512.11 करोड़ रुपए है। इनके बनने पर 71,967 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इसके साथ ही 125 मेगावाट बिजली पैदा होगी। राज्य सरकार आदिवासी अंचलों में वानिकी विस्तार, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, परंपरागत खेती के बजाय वृक्ष खेती को बढ़ावा देने के लिए वन विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। यह वन विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र की तर्ज पर ही वनों के विकास और उससे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने से जुड़े शोध कार्य भी करेगी। शुरुआती चरण में अगले पांच साल में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए कैबिनेट ने 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2025-26 के लिए सीएम ग्राम सड़क

एवं अवसंरचना योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित 10 लाख तक लागत वाले कार्यों की स्वीकृति की अनुमति दे दी है। इसके बाद 693.76 करोड़ के 3,810 विकास कार्य प्रदेश में किए जा सकेंगे। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 905.25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें 18-45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक बैंक लोन दिलाया जाता है। मेट्रो प्रोजेक्ट में घाटा 90.67 करोड़: भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल अनुमानित वित्तीय घाटा 90.67 करोड़ आया है। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्व मद में 90.67 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है।

सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट वापस: विधायकों और किसान संघ के विरोध के बाद झुकी सरकार

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट आखिरकार सरकार ने वापस ले लिया है। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सीएम हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। बैठक के बाद किसान संघ के पदाधिकारियों ने दावा किया था कि लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया जाएगा। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। दो दिन बाद 19 नवंबर को सरकार ने एक संशोधन आदेश जारी किया।

इसमें कहा गया कि अब स्थायी अधिग्रहण बिल्डिंग निर्माण के लिए नहीं होगा, बल्कि केवल सड़क, नाली जैसे बुनियादी विकास कार्यों के लिए ही जमीन ली जाएगी, लेकिन इस संशोधन पर भी भारतीय किसान संघ और कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पूरे एक्ट को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। मामला तब और गंभीर हो गया, जब 15 दिसंबर को उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। विधायक ने चेतावनी दी थी कि अगर एक्ट वापस नहीं लिया गया तो वे किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। विधायक के पत्र के अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। इस तरह सीएम से किसान संगठनों की मुलाकात के 29 दिन बाद सरकार ने यह फैसला लेते हुए सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट

को खत्म कर दिया। लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है। लेकिन उज्जैन में इस एक्ट को लेकर किसानों की आपत्ति यह रही कि जमीन देने की प्रक्रिया स्वेच्छिक नहीं लग रही, विकसित जमीन कब और कितनी मिलेगी, इस पर स्पष्टता नहीं है। सिंहस्थ और महाकाल लोक से जुड़े क्षेत्रों में जमीनों की कीमत बहुत अधिक है, ऐसे में किसान नुकसान की आशंका जता रहे हैं। कुछ गांवों में बिना पर्याप्त सहमति के सर्वे और नोटिस की बात सामने आई। इन्हीं कारणों से उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, ज्ञापन और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ा।



शशि थरूर, सावरकर व कैटल क्लास



पिछले सप्ताह खबर थी कि शशि थरूर ने सावरकर के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार को अस्वीकारा। क्यों? एक ओर वे हिंदू राजनीति का गुड खा रहे हैं, मोदी–पुतिन की दोस्ती की व्याख्या से लेकर सरकार की विदेश नीति और ‘मैं हिंदू क्यों हूं’ जैसी वैचारिक प्रस्तुति है वही दूसरी ओर, कांग्रेस और केरल की राजनीति में वे पैतरे हैं, जिनसे कमल खिले और कांग्रेस सिमटे। तब फिर सावरकर के नाम से परहेज क्यों? मामला वही है, गुड खाना है, पर गुलगुली से दूरी बनाए रखनी है। सवाल है कि थरूर को सावरकर के नाम और उनका तस्वीर से एलर्जी है, या उस हिंदू राजनीति की थीसिस से, जिसे आज हिंदुत्व की झंडाबढ़ाव जमात ने अपने क्रब्धे में ले लिया है? कारण शायद मनोवैज्ञानिक है। शशि थरूर स्वतंत्रता बाद की उस पहली पीढ़ी की वह प्रतिनिधि शख्सियत है जो नेहरू के आर्डिंडया ऑफ इंडिया के जमाने के प्रभुवां की कुलीनताओं में पली और बढ़ी है। थरूर दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़-लिख करियरवादी बुनावट में आईएससी की बजाय अमेरिका–संयुक्त राष्ट्र के मौकों से डिप्लोमेत रहे। अब कूटनीतिज्ञ भी शब्दों, भाषा के खिलाड़ी, बढ़ई होते है। विशेषकर वे बौद्धिक, जिनका दिमाग मूल मातृभाषा पर औपनिवेशिक, याकि पराई भाषा की परत में पढ़ते–लिखते और बोलते हैं। खांटी शब्दों में–मैकॉले की संतानों की मनोदश का यह वह स्थायी सत्व-तत्व है जो बिजनेस क्लास से सांस, सूकून पाता है और उसके लिए बाकी कैटल क्लास के मनुष्य।

मैं भी उम्र की कसौटी में स्वतंत्रता-उपरांत की पहली पीढ़ी का प्रतिनिधि हूं। मेरा संयोग है जो मेरी मौलिकता मातृभाषा से पोषित है और मैंने 1975 में जेएनयू, पत्रकारिता में बेनेट कोलमैन की शुरुआत से, लुटियन दिल्ली की पत्रकारिता में पहुंच आदि के जरिए अंग्रेजीदां शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, दूनु टोली आदि से लेकर अंग्रेजीदां श्रीश मुलगांवकर, जॉर्ज वर्गीज, अरुण शौरी सहित कैबिनेट सचिव, आईएएस, आईफएस पर जहां बारीकी से गौर किया है वहीं अपने खुद के हॉस्टल साथी या पत्रकार सतीश झा, सीताराम येचुरी, रविशंकर की संगत में बखूबी जाना-बूझा है कि अंग्रेजीदां प्लेट जमात का बिजनेस क्लास भाव कैसी-कैसी चाहनाओं, रां-रूप, इच्छाओं–आकांक्षाओं से बना होता है।

हिसाब से इसमें कुछ बुरा नहीं है। यों भी भारत का इतिहास गवाह है कि दिल्ली और

भारत, और खासकर हम हिंदू, सदा-सनातनी वर्ण–वर्ग से अधिक बिजनेस क्लास

बनाम कैटल क्लास का वह विभाजन लिए रहे हैं, जिसकी प्रभु-वर्गीय देवभाषा

संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेजी रही है, वहीं आमजन पाली, हिंदुस्तानी, हिंदी, क्षेत्रीय

भाषाओं, बोलियों से गुज़ारा करता आया है। मातृभाषा–मातृबुद्धि बनाम सत्ता-भाषा–

प्रभुवर्गीय बुद्धिका सनातन संस्कृति में अंतराल न कभी घटा और न कभी मिया।

इसलिए बिजनेस भी देशज, स्वभाषा में कैटल क्लास की आकांक्षाओं में अपनी देशज

राजनीति की, वे सर्वव लुटियन दिल्ली में अमान्य रहे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू का

आर्डिंडया ऑफ इंडिया चूँकि सत्ता की भाषा–बुद्धि–चिंतन का खूंट था, तो बौद्धिकता

में उस मैकाले मानस का एकाधिकार बनाना ही था जो सत्ता की भाषा याकि अंग्रेजी में

सोचे, बोले, लिखे। तभी स्वतंत्र भारत में सावरकर अछूत थे और संघ–जनसंघ की

राजनीति टिमटिमाती हुई थी।

तभी अटल बिहारी वाजपेयी यह सोच फड़फड़ाते थे कि जाएं तो जाएं कहां! वही

2014 से पहले नरेंद्र मोदी का रंग में कटाक्ष था–वाह, क्या गर्लेफ़िंड है, आपने कभी

देखा है पचास करोड़ की गर्लेफ़िंड! और मैंने वह समय प्रत्यक्ष देखा है जब संसद में

स्पीकर मनोहर जोशी की लगभग ज़िद से सेंट्रल हौल में सावरकर की तस्वीर जब

लगाई गई, तब कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर एंड पार्टी ने इस शिद्दत से विरोध किया

था मानों संसद भवन अपवित्र हुआ हो। इस नाने मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर

की बौद्धिकता का एक ही स्तर, एक सा विन्यास, एक ही खूंट है। मैं बिजनेस क्लास

बनाम कैटल क्लास का रूपक बार-बार इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि हवाई

यात्रा के सफर को लेकर शशि थरूर ने ही ऐसे कहा था।

तो शशि थरूर और सत्ता–पावर पोषित नेहरू के आर्डिंडया ऑफ इंडिया के रंग में

ढली-बनी बुद्धि आदतन सत्ता की भूख लिए हुए है। इसलिए मोदी राज में अवसर

तलाशने की फड़फड़ाहट है, मगर कैटल क्लास में बैठने, उसके पूजनीय को अपना

पूजनीय मानने का मन नहीं करता। शर्म आती है। असंभव नहीं है, पर कल्पना करें—

संघ प्रोग्राम में मोहन भागवत का बौद्धिक सुनते हुए शशि थरूर को। या थरूर को

मोदी द्वारा यह ज्ञान दिया जाना कि मैं तुम्हे समझाता हूं कि तुम क्यों हो हिंदू? थरूर ने

पिछले ग्यारह वर्षों में अपने को हिंदू बतलाने की कई कोशिशें की हैं। अवसरवाद के

औचित्य बनाए हैं। भय, भूख, भक्ति के उपक्रम किए हैं। लेकिन सावरकर को लेकर

इनकार या दुविधा का जो भाव हाल में दर्शाया है, वह भारत की बौद्धिकता का वह

राष्ट्रीय खोखलापन है जो मौजूदा संक्रमण काल में आए गाढ़ा होते हुए है। इसलिए

क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक घोषणा की है कि ज़माना हार्वर्ड याकि बुद्धि का

नहीं, हार्ड वर्क का है—और भाजपा–संघ के लिए यह परम पूजनीय, आदरणीय

प्रातः स्मरणीय ज्ञान सूत्र है। एक और सत्य व तथ्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी

सौर्वीं वर्षगांठ तक भी सरकार से जब सावरकर, डेडेगोवार, गोलवलकर या कपरात्री

में से किसी को भी भारत रत्न से पुरस्कृत नहीं कर पाया और वे जस के तस लुटियन

दिल्ली में अमान्य हैं, तो भला शशि थरूर क्यौंकर सावरकर का महिमामंडन करें? मान

लें, शशि थरूर सावरकर अर्बोंड ले लेते। अपने ऊपर सावरकरवादी होने का

ठण्पा लगाव लेते तो इससे प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या उपयोगिता बनती? केरल

उनके चेहरे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। और थरूर के डाक टिकट आकार के

फोटो से भाजपा विधानसभा चुनाव जीत भी जाए, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी, अमित

शाह के खाते में ही जमा होगा। भाजपा में अब बुद्धिजीवी, ज्ञानी या हार्वर्ड के चेहरे

श्रेय के कैसे हकदार हो सकते हैं? थ शरूर ने जब बिजनेस क्लास बनाम कैटल

क्लास का फर्क बताया था, तब उसके पीछे उनका एक बौद्धिक अहंकार भी था।

–हरिशंकर व्यास

विपक्ष अपनी हार का खुद जिम्मेदार है

अब तक हजारों ईवीएम मशीनों के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्चियों के साथ किया गया है और अपवाद के लिए भी एक गड़बड़ी नहीं मिली है। ये वीवीपैट मशीनें रैंडम चुनी जाती हैं और आज तक एक भी गड़बड़ी नहीं मिली है इसका मतलब है कि इससे मतदान सौ फीसदी सुरक्षित है। फिर भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को बैलेट पेपर से मतदान कराना है ताकि अपराधी किस्म के लोगों की मदद से बूथ लूटा जा सके, जैसा पहले होता था। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां संसद के मानसून सत्र के समय से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा के लिए बैचैन थीं। सरकार ने उस पर चर्चा काटा दी। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई और विपक्ष की कमजोरी खुल कर सामने आ गई। कांग्रेस और विपक्ष की तुष्टिकरण की नीति की पोल भी वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान खुल गई। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चर्चा की शुरुआत की और करीब डेढ़ घंटे के भाषण में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के दोहरे रवैए को एक्सपोज किया। रही सही कसर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूरी कर दी। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के ऐसे नेताओं को एक सूची ही आसन को सौंप दी, जिनको वंदे मातरम् गाने से आपत्ति रही है। इसके बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई, जिसमें अमित शाह ने आजादी के पहले से शुरू हुई वोट चोरी की पोल खोली।

कांग्रेस नेताओं के पास इस बात का जवाब नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस की 15 प्रतीय कमेटियों में से किसी ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव किया। सबको पता था कि 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, अंग्रेज उसी को सत्ता सौंपेंगे, वही अंतरिम सरकार का प्रमुख बनेगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख के लिए सबकी पसंद सरदार पटेल थे लेकिन अध्यक्ष बने पंडित नेहरू। क्या यह वोट चोरी की मिसाल नहीं है? इसके बाद भाजपा और एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने बूथ लूट से लेकर वोट चोरी तक के अनेक किस्से सुनाए। यह भी बताया गया कि कैसे पहले चुनाव में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की सीट पर 70 हजार से ज्यादा वोट अमान्य किए गए और बाबा साहेब अंबेडकर 15 हजार से कम वोट से हारे। ऐसे किस्सों के बाद कांग्रेस के पास मुंह छिपाने को जगह नहीं थी।

चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव सुधार के नाम पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस को हटाने का फैसला बहुत गलत था। सवाल है कि चीफ जस्टिस कम इस पैनल के सदस्य बने? वह तो जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना देती है तब तक एक अंतरिम कमेटी रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस सदस्य होंगे। जब संसद ने कानून बनाया तो उसने बाकी पदों पर नियुक्ति के लिए जो पैनल है उसी तरह का पैनल चुनाव आयोग के लिए भी बना दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सरकार के एक मंत्री सदस्य हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी याद दिलाते हुए कहा कि आजादी के बाद 73 साल तक तो प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था। अब तो कम से कम तीन सदस्यों की कमेटी है, जिसमें एक सदस्य विपक्ष का है। यानी 33 फीसदी हिस्सा विपक्ष का। पहले तो विपक्ष का एक फीसदी भी हिस्सा नहीं होता था। जहां तक चुनाव आयोग की साख बिगाड़ने का सवाल है तो क्या किसी को इस बात



से इनकार हो सकता है कि यह काम कांग्रेस ने किया है? कांग्रेस ने सबसे पहले रिटायर मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यसभा भेज कर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया था। कांग्रेस नेता बड़ी सुविधा से अपना यह इतिहास भूल जाते हैं। चुनाव सुधार के नाम पर विपक्ष की ओर से ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की गई। यह मांग इस तथ्य के बावजूद की गई कि आज तक विपक्षी पार्टियां ईवीएम की एक भी गड़बड़ी साबित नहीं कर पाई हैं या एक भी भरोसेमंद सबूत नहीं पेश कर पाई हैं। ध्यान रहे चुनाव आयोग खुद ही ईवीएम से होने वाली वोटिंग को फुलप्रूफ करने के लिए समय समय पर बदलाव करता रहता है। इसी के तहत ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें जोड़ी गईं, ताकि लोग परची पर यह देख सकें कि उन्होंने जिसको वोट दिया है, वोट उसी को गया है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में पांच बूथों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोट से किया जाता है। अब तक हजारों ईवीएम मशीनों के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्चियों के साथ किया गया है और अपवाद के लिए भी एक गड़बड़ी नहीं मिली है। ये वीवीपैट मशीनें रैंडम चुनी जाती हैं और आज तक एक भी गड़बड़ी नहीं मिली है इसका मतलब है कि इससे मतदान सौ फीसदी सुरक्षित है। फिर भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को बैलेट पेपर से मतदान कराना है ताकि अपराधी किस्म के लोगों की मदद से बूथ लूटा जा सके, जैसा पहले होता था। कितनी हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लगातार बड़े सुधारों की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्ष को एक भी सुधार कबूल नहीं है। सरकार ने तीन सबसे बड़े सुधारों की पहल की है। इसमें सबसे पहले 'एक देश, एक चुनाव' की बात की जा सकती है। सरकार ने इसका बिल संसद में पेश किया, जिस पर अभी संयुक्त संसदीय समिति में विचार हो रहा है। विपक्षी पार्टियां इस सुधार का विरोध कर रही हैं। दूसरा बड़ा सुधार परिसीमन का है, जो अगले साल शुरू हो रही जनगणना के बाद होगा। गौरतलब है कि अगले साल अप्रैल से सितंबर तक पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और फरवरी 2027 में आबादी की गणना होगी।

इसमें जातियां भी गिनी जाएंगी। इसके बाद परिसीमन का काम होगा। विपक्षी पार्टियां परिसीमन का भी विरोध कर रही हैं। तीसरा बड़ा सुधार सरकार कर चुकी है और वह है नारी शक्ति वंदन कानून, जिसके तहत महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

चौथा सुधार चुनाव आयोग कर रहा है और वह है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चल रहा है। बिहार में एसआईआर के बाद मतदान हुआ और अभी 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है।

दरवाजा खोलना काफी नहीं

भारत में 2.8 प्रतिशत लोगों के पास जीवन बीमा और एक फीसदी लोगों के पास सामान्य बीमा पॉलिसी है। प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की संख्या पांच प्रतिशत से कम है। बाकी लोग पॉलिसी का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर केंद्र ने हाल में अनेक ऐसे फैसले लिए हैं, जिनके जरिए संदेश भेजने की कोशिश हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार तीव्र गति से अगले चरण के “आर्थिक सुधारों” को लागू कर रही है। इस दिशा में जीएफस्टी दरों में हेरफेर और चार श्रम संहिताओं पर अमल के बाद अब बीमा क्षेत्र में उदारीकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने नए बीमा विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत इस क्षेत्र को 100 फीसदी विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में निवेश संबंधी अनेक प्रमुख शर्तों को आसान करने का निर्णय लिया गया है। आशा की गई है कि इससे बड़े पैमाने पर बाहरी निवेश आएगा, जिससे कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



में लगातार हालिया गिरावट से उपजी समस्या से राहत मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? अगर पिछले अनुभव पर ध्यान दें, तो इसकी संभावना कम लगती है। 2021 में

केंद्र ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 49 से 74 फीसदी की थी। मगर उससे फैसेल से विदेशी बीमा कंपनियां भारत की ओर आकर्षित नहीं हुईं। ना ही भारतीय

विपक्षी पार्टियां ऐंडी चोटी का जोर लगा कर एसआईआर का विरोध कर रही हैं। कई नेताओं की ओर से जनता को उकसाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन हर जगह नागरिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से एसआईआर में हिस्सा लिया। कुछ राज्यों में बड़ी आबादी के हिसाब से एसआईआर की सीमा बढ़ाई गई है तो कुछ राज्यों में इसका पहला चरण पूरा हो गया।

पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर को पहला चरण पूरा हुआ। अखिरी दिन मुख्यमंत्री सु ममता बनर्जी ने भी अपना मतदाता प्रपत्र भर कर जमा कराया। 16 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी होगी। उससे पहले चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख नाम कट सकते हैं। ध्यान रहे बिहार में कुल 69 लाख नाम कट थे। गौरतलब है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग बराबर है। फिर भी पश्चिम बंगाल में बिहार के मुकाबले 11 लाख कम नाम कटने की संभावना है।

यह आम धारणा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैटियों और अवैध मतदाताओं की संख्या बिहार या किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। फिर भी बिहार से कम नाम कट रहे हैं! यह हैरानी की बात है। क्या इसका कारण यह है कि बिहार में एसआईआर शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों के जन्म प्रमाणपत्र और आवास प्रमाणपत्र बनाए गए हैं? चुनाव आयोग को इस पर नजर रखनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इस बात की जांच करे कि पिछले छह महीने में जिन लोगों के जन्म और आवास प्रमाणपत्र जारी हुए हैं वे सही हैं या नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग को उनसे किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र की मांग करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही प्रमाणपत्र है और वह छह महीने पहले बना है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इस मामले में सख्ती नहीं करेगा तो फिर इतनी बड़ी कवायद के बावजूद कुछ न कुछ गड़बड़ी रह जाएगी।

बहरहाल, यह संयोग नहीं है कि विपक्ष को हर चुनाव सुधार से दिक्कत है। उसे परिसीमन से दिक्कत है तो 'एक देश, एक चुनाव' से भी दिक्कत है और मतदाता सूची के शुद्धिकरण से भी दिक्कत है। असल में विपक्षी पार्टियों को अपनी हार छिपाने का एक बहाना इन बातों में मिल गया है। विपक्षी पार्टियां इसलिए हार रही हैं क्योंकि उनके पास न तो नेता है, न नीति है और न नीयत है। उनके पास संगठन नहीं है और देश के विकास की कोई रूपरेखा नहीं है इसलिए देश की जनता उनको लगातार खारिज कर रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है, जिसने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है और देश को तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। भारत अब विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए लोग निरंतर भाजपा को चुन रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को पता है कि वे अपनी कमजोरी के कारण हार रही हैं लेकिन वे कभी ईवीएम पर तो कभी मतदाता सूची पर तो कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती हैं ताकि अपनी कमजोरियों पर परदा डाला जा सके। देश की जनता इस बात को समझ गई है इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

–एस. सुनील (लेखक दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ताम्गं (गोले) के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विशेष कार्यवाहक अधिकारी हैं।)

कंपनियों के साथ साझा उद्यम में उनके निवेश में कोई ठोस बढ़ोतरी हुई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जब से बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला गया, लगभग 82 हजार करोड़ रुपये का बाहरी निवेश आया है। लेकिन यह अधिकांशतः भारतीय कंपनियों के साथ साझा उद्यम में आया। मुमकिन है, ताजा फैसले से वैसे निवेश में कुछ बढ़ोतरी हो। मगर भारतीय बीमा बाजार के मूल ढांचे में किसी गुणात्मक परिवर्तन की संभावना कम ही है। इसका कारण इस बाजार का सीमित आकार है। भारत में 2.8 प्रतिशत लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा हासिल है। सामान्य बीमा की पैठ तो महज एक फीसदी आबादी तक है। प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की संख्या भी पांच प्रतिशत से कम ही है। बाकी लोगों की जब किसी तरह की बीमा पॉलिसी का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। जब तक यह सूरत नहीं बदलती, बीमा कंपनियां क्यों निवेश बढ़ाएंगी? वह स्थिति कैसे बदले, और किसी कोई दृष्टि सरकार ने सामने नहीं रखी है।

प्रबंध के घमंड की वजह से इंडिगो संकट !



और केबिन कू की गंभीर कमी सामने आई। लागत कटौती के लिए स्टाफ संख्या को न्यूनतम रखने की रणनीति तब उलटी पड़ गई। इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स ने स्वीकार किया है कि सामान्य परिचालन धीरे-धीरे ड्यूटी नियमों से अस्थायी छूट मांग रही है। सवाल यह उठता है कि जब डीजीसीए ने सभी ऑपरेटरों को नए नियमों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया था, तो इंडिगो ने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला क्यों लिया? भारत के विमानन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निजी एयरलाइनों का पतन प्रबंधन की विफलताओं और बाहरी दबावों के कारण हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी देश की सबसे चमकदार सेवा थी, वित्तीय कुप्रबंधन और अत्यधिक कर्ज के कारण 2012 में अचानक बंद हो गई। जेट एयरवेज, जो भारत के निजी

लागत बचत को पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालन आवश्यकताओं से ऊपर रखती हैं, वे एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर अचानक ढह जाती हैं। इंडिगो संकट, एयरलाइन प्रबंधन और नियामकीय निगरानी दोनों की प्रत्याशा में रौस्टर समायोजित करके और अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करके इसी तरह के व्यवधानों से बचाव किया। सोचने वाली बात है कि यह संकट कम किया जा सकता था या पूरी तरह टाला जा सकता था, यदि इंडिगो ने स्टार्फिंग और अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया होता। डीजीसीए द्वारा सख्त अनुपालन ऑडिट की अनुपस्थिति ने भी इस अराजकता में भूमिका

विमानन युग का अग्रदूत था, 2019 में नियम पुस्तिका के उल्लंघनों, खराब वित्तीय नियंत्रणों, बढ़ते घाटे और बदलते बाजार हालातों से अनुकूलन में असमर्थता के कारण इसी भाग्य का शिकार हुआ।

इंडिगो का नए एफडीटीएल नियमों को नजरअंदाज करने का तरीका भी जेट एयरवेज की याद दिलाता है, जो इसी तरह के घमंड के चलते अपनी सुविधा के लिए नियमों को अनदेखा करती रही। ये उदाहरण एक दोहरावदार पैटर्न को रेखांकित करते हैं: वे एयरलाइंस जो अल्पकालिक

निभाई। भविष्य के संकटों को रोकने के लिए, एयरलाइंस को परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए, पर्याप्त स्टार्फिंग में निवेश करना चाहिए और नियामकीय निकायों तथा कर्मचारी यूनियनों के साथ खुले संवाद बनाए रखने चाहिए। परिचालन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, डीजीसीए को ऑपरेटरों से सुझाव भी लेने चाहिए ताकि उनकी मांगों को समायोजित किया जा सके। इंडिगो का संकट सिर्फ एक एयरलाइन की गलतियों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। इंडिगो संकट के मद्देनजर डीजीसीए द्वारा सख्त नियामकीय कार्रवाई भारत में एयरलाइन उल्लंघनों के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम कर सकती है। डीजीसीए ने पहले ही सामूहिक रद्दीकरणों की परिस्थितियों की जांच के लिए एक व्यापक जांच शुरू कर दी है, जिसमें चार सदस्यीय पैनल को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है ताकि प्रवर्तन कार्रवाइयों और संस्थागत सुधारों की सिफारिश का जा सके। पिछले उदाहरण दिखाते हैं कि नियामक ने अनुपालन न करने के लिए कठोर दंड लगाने में संकोच नहीं किया, जिसमें 10 लाख से 90 लाख रुपये या इससे अधिक के वित्तीय जुर्माने, ऑपरेटर अनुमतियों का निलंबन और बार-बार या गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, डीजीसीए ने हाल ही में एयर इंडिया को एक पायलट को अनिवार्य नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उड़ान संचालित करने की अनुमति देने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ऐसे दंडों को लागू करके और एयरलाइंस तब उनके प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराकर, डीजीसीए एक स्पष्ट संदेश है: परिचालन शॉर्टकट, नियामकीय अनुपालन न करने और लापरवाही को त्वरित और सख्त परिणामों से सामना करना पड़ेगा। इंडिगो का संकट बताता है कि परिचालन उच्छुद्धता सिर्फ दक्षता और समय की पाबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि एयरलाइन कू व यात्री सुरक्षा, तैयारी और जिम्मेदारी के बारे में भी है।

–रजनीश कपूर



पीओके में क्यों भड़का विरोध प्रदर्शन, रावलकोट में सड़कों पर अवाम, पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी



एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन भड़क गया है। रावलकोट में मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने पीओके में बिजली की अनुचित कटौती, खराब मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के खिलाफ और पत्रकार सोहराब बरकत की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया था।

इस प्रदर्शन के दौरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन को कड़ा संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके की सरकार को शाम 5:00 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिजली सप्लाई में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीओके में बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इसका लाभ दूसरे सूबों को दिया जा रहा है और यहां के लोग इससे महरूम हैं। लोगों ने पीओके में

मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी सुधारने की मांग की। सीमावर्ती इलाका होने के कारण पाकिस्तान ने पीओके में बड़े पैमाने पर इंटरनेट पारबंदियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा लोग एक स्थानीय पत्रकार सोहराब बरकत की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। घोषणा के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें न मानी गईं तो दो मुख्य रास्ते बंद किए जा सकते हैं। इमें एक ग्रिड स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता है और दूसरा शाहराह-ए-गाड़ी मिल्लत की ओर जाने वाला रास्ता। उन्होंने पीओके के अन्य इलाकों में भी लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में फिर अड़ंगा, लंदन कोर्ट में सुनवाई अगले साल मार्च तक टली

एजेंसी लंदन

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण अपील पर सुनवाई मंगलवार को अगले साल मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में अपनी प्रत्यर्पण अपील पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। मामले की सुनवाई मुंबई में नीरव मोदी की हिरासत के संबंध में भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन के बाद स्थगित की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि प्रत्यर्पण के लिए कानूनी बाधा से संबंधित एक 'गोपनीय प्रक्रिया' (जिसे आश्रय आवेदन माना जाता है) संभवतः अगस्त में विफल हो गई थी। पंजाब



नेशनल बैंक ऋण घोटाला मामले में अदालत में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही 'क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस' ने तर्क दिया कि प्रत्यर्पण अपील पर फिर से विचार किए जाने का आवेदन उस 'गोपनीय प्रक्रिया' के कथित तौर पर समाप्त हो जाने के कुछ ही दिनों बाद तत्काल रूप से

सामने आया। नीरव मोदी को उत्तरी लंदन की पेटोनविल जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। यदि मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाली दो दिवसीय सुनवाई के दौरान इस अपील को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो भारत में उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाने की उम्मीद है।

पाकिस्तानी सेना के गढ़ रावलपिंडी से मिट गई हिंदू विरासत, कभी बहुसंख्यक थे, अब अस्तित्व भी खत्म, 39 मंदिरों में अब सिर्फ 3 बाक़ी



एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तान का रावलपिंडी एक वक्त हिंदुओं का शहर हुआ करता था, मंदिरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब इस शहर की हिंदू पहचान लगभग मिट चुकी है। रावलपिंडी शहर का इतिहास करीब एक हजार सालों से ज्यादा का रहा है और एक वक्त ये हिंदू सभ्यता का केन्द्र हुआ करता था। उस वक्त यहां रहने वाले हिन्दुओं को अगर कोई कहता कि तुम्हारा अस्तित्व इस शहर से मिटा दिया जाएगा, वो तो उसी तरह से हंसते और ऐसा दावा करने वालों का मजाक उड़ाते, जैसा आज कुछ लोग करते हैं। 1947 से पहले यह शहर मंदिरों, धर्मशालाओं और हिंदू बहुल मोहल्लों से भरा था। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 1943 की जनगणना के मुताबिक, रावलपिंडी में 82,178 हिंदू, 47,963 सिख और सिर्फ 22,461 मुस्लिम रहते थे। उस समय रावलपिंडी में 39 मंदिर, 14 गुरुद्वारे, 12 श्मशान घाट और 11 धर्मशालाएं मौजूद थीं। डिंगी खोई, पुराना किला, जामिया मस्जिद रोड, नेहरू रोड (अब गजनी रोड), सह्र और रेलवे रोड जैसे इलाके हिंदू आबादी के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद हालात तेजी से बदले और हिंदू समुदाय के एक बड़े हिस्से को मार पीटकर भारत भगा दिया गया। हिंदुओं के जाने के बाद थोड़े बहुत सिख, जो बच गये थे, उन्हें इन

इलाकों में बसाया गया। धीरे धीरे रावलपिंडी से पारसी समुदाय के लोगों को भी भगा दिया गया। पारसी समुदाय के कुछ लोग कराची तो ज्यादातर लोग भारत और ईरान भागकर चले गये। अब रावलपिंडी से पारसी आबादी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में आज की तारीख में सिर्फ 5 हजार 113 हिंदू बचे हैं, जबकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिर्फ 141 हिन्दू परिवार रहते हैं। रावलपिंडी में अब सिर्फ तीन मंदिर हैं, जहां पूजा होती है, जिनमें एक कृष्ण मंदिर (सदर इलाके में), वाल्मीकि मंदिर (ग्रेसी लाइन्स) और लाल कुर्ती मंदिर शामिल हैं। ये तीनों मंदिर सौ साल से ज्यादा पुराने हैं, इसीलिए अब ये भी जरूर होने लगे हैं। इनके अलावा कल्याण दास मंदिर, देवी मंदिर (कोहाटी बाजार), और पुराना किला मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब इन मंदिरों में पूजा करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा हिंदू समुदाय के लिए अभी कोई भी धर्मशाला या श्मशान घाट रावलपिंडी में नहीं है। हालांकि मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने, टीपू रोड के पास एक 80 साल पुराना श्मशान घाट जरूर है, लेकिन अब स्थानीय मुसलमानों ने इस श्मशान घाट में दाह संस्कार पर रोक लगा दी है। यहां अगर कभी दाह संस्कार होता भी है तो भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। 1947 से पहले, शहर में नौ बड़े हिंदू और सिख स्कूल चलते थे, जिनपर अब पाकिस्तान की

सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। करीब एक सदी तक रावलपिंडी पर राज करने वाला हिंदू समुदाय अब खत्म हो गया है और इस्लामिक देश पाकिस्तान में अब भला उनकी कौन सुनेगा! हिंदू-सिख वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष सरदार हीरा लाल ने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए फंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या श्मशान घाट का न होना है। उन्होंने द ट्रिब्यून से कहा कि “हम अनुरोध करते हैं कि शहर के बाहर 4-5 कनाल जमीन दी जाए जहां हम एक श्मशान घाट, एक धर्मशाला और पूजा के लिए एक छोटा मंदिर बना सकें। हम वफादार पाकिस्तानी हैं, हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए थे। 1947 के बाद, भारत ने आकर्षक ऑफर दिए थे, लेकिन हमने मना कर दिया। रावलपिंडी हमारी जन्मभूमि है। हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते।” वहीं, लाल कुर्ती मंदिर के संरक्षक और हिंदू-मुस्लिम-सिख यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि समुदाय को 7-10 प्रतिशत नौकरी और शिक्षा कोटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि बंद मंदिरों को फिर से खोला जाए और रखरखाव के लिए हिंदू समुदाय को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने, खासकर दिवाली और होली जैसे त्योहारों के दौरान, बहुत सम्मान और सहयोग दिखाया है। कुल मिलाकर रावलपिंडी की कभी समृद्ध हिंदू विरासत आज धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गई है।

भारत ने तालिबान से निभाई दोस्ती, अफगानिस्तान को शुरू किया दवाओं का एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को बड़ा झटका



एजेंसी काबुल

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत से दवाओं का आयात शुरू कर दिया है। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की दवाओं की गुणवत्ता खराब है और वे अफगान लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब काबुल की एक प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधियों ने एक जानी-मानी भारतीय कंपनी के ब्रांच ऑफिस के उद्घाटन के साथ भारत से अफगानिस्तान में दवाओं के ऑफिशियली इंपोर्ट शुरू होने की घोषणा की है। हुरियत रेडियो इंग्लिश के X पोस्ट के अनुसार, शुरुआती दौर में, 25 तरह की दवाएं इंपोर्ट की जाएंगी। इसमें भविष्य में अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने पुष्टि की कि देश में फिलहाल 400 से ज्यादा कंपनियां दवाओं के इंपोर्ट में लगी हुई हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की

दवाएं हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि एक भारतीय कंपनी के अधिकारियों ने दवा उत्पादन में अपने 90 सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, हेल्थकेयर सेक्टर में अफगानिस्तान के साथ लगातार सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तालिबान प्रशासित सरकार के पाकिस्तान से दवाओं के इंपोर्ट पर रोक लगाने के बाद, इंपोर्ट करने वालों को दवाएं हासिल करने के लिए दूसरे रास्ते खोजने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद भारत से दवाओं के इंपोर्ट की यह ठोस पहल शुरू हुई। पाकिस्तानी दवा निर्माता कंपनियां हर साल अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में दवाओं का निर्यात कर भारी मुनाफा कमाती थीं। उनकी दवाओं की गुणवत्ता निम्नस्तर की होती थी। इससे पाकिस्तानी कंपनियों की लागत कम आती थी, लेकिन वे अफगानिस्तान को पूरी कीमत पर दवाओं का निर्यात करती थीं। इससे अफगान लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। अब तालिबान सरकार के प्रतिबंध से पाकिस्तानी दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया है। ऐसे में उन्हें दूसरे अल्टरनेटिव को देखना होगा, जहां माल पहुंचाने का लागत अफगानिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा होगा।

भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस क्यों गया था सिडनी बॉन्डी बीच का शूटर, सैन्य ट्रेनिंग और इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन पर सवाल

एजेंसी सिडनी

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में शामिल दो हमलावरों में से एक ने फिलीपींस की यात्रा की थी। इसके लिए उसने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। ऑस्ट्रेलियाई जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश रहा है कि क्या उसने इस यात्रा के दौरान फिलीपींस में चरमपंथी इस्लामिक उपदेशकों से मुलाकात की थी और क्या उसे यहीं पर मिलिट्री स्ट्राइल हमले की ट्रेनिंग भी मिली थी या नहीं। साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला मना रहे यहूदियों को निशाना बनाया था। इस हमले में 16 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 साल की लड़की और एक 87 साल का आदमी शामिल था जो हिटलर के होलोकॉस्ट से बच गया था। बाद में पुलिस की गोलीबारी में इनमें से एक हमलावर मारा गया और दूसरे को गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया

गया। बीबीसी ने मनीला के अधिकारियों के हवाले से बताया, “उन्होंने 1 से 28 नवंबर के बीच उस देश (फिलीपींस) की यात्रा की, जिसके बाद ऐसी खबरें आई कि वे 'मिलिट्री-स्ट्राइल ट्रेनिंग' लेने गए थे।” बीबीसी की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, “साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की और उसके बेटे, नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।” ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी ने मनीला के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया कि साजिद अकरम पिछले महीने भारतीय पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से फिलीपींस गया था। रॉयटर्स ने भी अधिकारियों के हवाले से बताया कि “पिता ने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर था।” सुरक्षा विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि अकरम का संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन साजिद को भारतीय पासपोर्ट कैसे मिला, यह अब मुख्य सवाल है। फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा चरमपंथी मौलवियों और इस्लामी आतंकवादी समूहों का गढ़ रहा है। वहां कई सशस्त्र इस्लामी संगठनों ने इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा जताई है।

ऑस्ट्रेलियन बॉड्कास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) के अनुसार, पिता-पुत्र की जोड़ी “मिलिट्री-स्ट्राइल ट्रेनिंग” लेने के लिए फिलीपींस गई थी। वे नवंबर की शुरुआत में फिलीपींस पहुंचे थे। एक वरिष्ठ आतंकवाद विरोधी अधिकारी ने एबीसी को बताया, “नवीद और साजिद अकरम ने फिर दक्षिणी फिलीपींस की यात्रा की और आतंकवादी प्रशिक्षण लिया।” एबीसी रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या साजिद और नवीद अकरम किसी अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क से जुड़े थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि बॉडी बीच हमला “इस्लामिक स्टेट की विचारधारा” से प्रेरित था। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने बीच के पास नवीद के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के अलावा IS के दो हाथ से बने झंडे बरामद किए। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे नवीद पर 2019 में IS से संबंध संबंधों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी, लेकिन कथित तौर पर उसे बिना निगरानी के छोड़ दिया गया था।



गुजरात टाइटंस ने 12 करोड़ के पर्स से किन्न खिलाड़ियों को किया शामिल, खतरनाक दिख रहा है स्क्वाड

एजेंसी नई दिल्ली

आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर अपनी चिर-परिचित रणनीति का प्रदर्शन किया, जो बड़े और नाटकीय बदलावों के बजाय स्थिरता, संतुलन और लक्षित खरीद पर आधारित थी। ऑक्शन से पहले ही कप्तान शुभमन गिल, स्टार स्पिनर राशिद खान, सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और तेज गेंदबाजी कोर में मोहम्मद सिराज व कागिसो रबाडा जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन करके, टाइटंस ने अपनी मजबूत नींव को बरकरार रखा था। मात्र 12.90 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी गुजरात का उद्देश्य उन छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण, कमियों को भरना था जो उन्हें पिछले सीजन में महसूस हुई थीं खासकर मध्य क्रम और तेज गेंदबाजी में बैकअप के तौर पर। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी खरीद वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर (7 करोड़) के रूप में सामने आई। शेरफेन रदरफोर्ड को ट्रेड करने के बाद गुजरात को एक ऐसे विदेशी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश थी जो निचले क्रम में पावर हिटिंग कर सके और डेथ ओवरों में गेंदबाजी का विकल्प दे। होल्डर इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं और उनकी खरीद से टीम को महत्वपूर्ण लचीलापन मिला है। इसके अतिरिक्त, टाइटंस ने इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम बैटन को 2 करोड़ में खरीदा, जो शीर्ष क्रम पर एक विस्फोटक विकल्प प्रदान करते हैं और विकेटकीपिंग में जोस बटलर के लिए बैकअप का काम करेंगे। भारतीय अनकैप्ड प्रतिभाओं पर भी टाइटंस का निवेश देखने को मिला, जहां उन्होंने राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को 90 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। अशोक शर्मा ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में अपनी गति और विविधता से प्रभावित किया है और वह



भारतीय तेज गेंदबाजी पूल में गहराई जोड़ेंगे, जो आशीष नेहरा की कोचिंग शैली में निखर सकते हैं। इसके अलावा, टीम ने इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड (75 लाख) और घरेलू तेज गेंदबाज पृथ्वीराज यरा (30 लाख) को बेस प्राइस पर खरीदकर अपनी तेज गेंदबाजी इकाई को मजबूत किया, जो रबाडा और सिराज के लिए विश्वसनीय कवर प्रदान करेंगे। मिनी-ऑक्शन 2026 के बाद, गुजरात टाइटंस की टीम पहले से कहीं अधिक संतुलित और गहरी नजर आ रही है। शीर्ष क्रम में शुभमन गिल और साई सुदर्शन की निरंतरता, मध्य क्रम में शाहरुख खान और राहुल तेवतिया की फिनिशिंग क्षमता, तथा बटलर और बैटन जैसे पावर-हिटर, गुजरात की बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं। वहीं, गेंदबाजी में राशिद खान की विश्व स्तरीय स्पिन के साथ

सिराज, रबाडा और होल्डर जैसे खिलाड़ियों का मिश्रण उन्हें किसी भी परिस्थिति में एक दुर्जेय टीम बनाता है। यह स्पष्ट है कि गुजरात टाइटंस ने बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय, अपनी मौजूदा कोर टीम को मजबूत करने और प्रमुख भूमिकाओं के लिए विशेषज्ञ खिलाड़ियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे वे आगामी सीजन में एक बार फिर खिताब के दावेदार बन सकें। शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसीद्ध कृष्ण, इशांत शर्मा, गुरनुर सिंह बराड, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयन्त यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैटन, पृथ्वी राज, ल्यूक वुड।

आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब जिता देगा ये स्क्वाड, मिनी ऑक्शन में एक से एक खिलाड़ी किया शामिल

एजेंसी नई दिल्ली

आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम ने मिनी-ऑक्शन 2026 में बहुत सोच-समझकर खरीदारी की और अपनी मजबूत कोर टीम को बनाए रखने पर जोर दिया। 16.40 करोड़ रुपये के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी आरसीबी ने उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उन्हें पिछले सीजन में थोड़ी कमी महसूस हुई थी खासकर भारतीय ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजी विभाग में बैकअप के तौर पर। आरसीबी की ऑक्शन की सबसे बड़ी और निर्णायक खरीद भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर (7 करोड़) के रूप में सामने आई। पिछले सीजन में वेंकटेश की महंगी कीमत को देखते हुए, 7 करोड़ में उन्हें टीम में शामिल करना बेंगलुरु के लिए एक बड़ी सफलता

रही। वेंकटेश अय्यर न केवल शीर्ष क्रम में एक आक्रामक बल्लेबाजी विकल्प प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी कप्तान रजत पाटीदार को एक अतिरिक्त विकल्प भी देती है। इसके अलावा टीम ने न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जैकब डफी को उनके बेस प्राइस (2 करोड़) पर खरीदकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी, जो जोश हेजलवुड और नुवान तुषारा जैसे प्रमुख गेंदबाजों के लिए एक विश्वसनीय बैकअप का काम करेंगे। बेंगलुरु ने भारतीय अनकैप्ड प्रतिभाओं पर भी भरोसा जताया, खासकर मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज मंगेश यादव (5.20 करोड़) को बड़ी रकम देकर खरीदा। मंगेश, कप्तान रजत पाटीदार के राज्य के साथी हैं और उन पर किया गया यह निवेश यश दयाल के बैकअप और भारतीय तेज गेंदबाजी पूल की गहराई को बढ़ाने की आरसीबी की रणनीति का हिस्सा है।

इसके अलावा, टीम ने इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स (75 लाख) को शामिल किया, जो फिल साल्ट और जितेश शर्मा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगे, जबकि सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, और विक्की ओस्तवाल जैसे युवा अनकैप्ड खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदकर भविष्य के लिए बैंच स्ट्रेंथ तैयार की गई है। खिराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, कुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, नुवान तुषारा, रसिख डार, स्विनल सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, जॉर्डन कॉक्स।

प्रशांत वीर ने जताई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने की खुशी, धोनी को लेकर कही ये बात



एजेंसी नई दिल्ली

IPL 2026 की मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने वाले नए खिलाड़ी प्रशांत वीर ने टीम में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। प्रशांत वीर ने स्पष्ट किया है कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा टीम के मार्गदर्शक और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं और वह उनसे सीखने के लिए उत्सुक हैं। IPL नीलामी के बाद जियोस्टार पर बात करते हुए प्रशांत वीर ने धोनी के प्रभाव पर विशेष रूप से बात की। प्रशांत वीर ने कहा कि 'मैं चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर खुश हूँ क्योंकि एमएस धोनी वहां हैं। जिस तरह से वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, उनकी मानसिकता जिस तरह से वह बात करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं और इतने केंद्रित रहते हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है।' प्रशांत वीर को आईपीएल के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में

खरीदा है। यह आईपीएल इतिहास में किसी भी अनकैप्ड प्लेयर पर खर्च की जाने वाली सबसे ज्यादा रकम है। प्रशांत वीर ने निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका की कठिनाई को स्वीकार करते हुए धोनी की काबिलियत को खास बताया। उन्होंने कहा कि 'निचले क्रम में बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने (धोनी ने) जो किया है वह खास है। अगर मैं उनसे चार या पांच प्रतिशत भी सीख सकता हूँ, तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा।' प्रशांत वीर ने साफ कर दिया है कि उनका मुख्य ध्यान धोनी के खेलने के कौशल के साथ-साथ उनकी बेजोड़ मानसिक दृढ़ता और दबाव को संभालने की कला सीखने पर रहेगा। CSK के ड्रेसिंग रूम में धोनी की उपस्थिति प्रशांत वीर जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए एक अमूल्य सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिसका लाभ वह पूरी तरह उठाना चाहेंगे।

व्यापार

1 का केचप, 5 में नूडल्स...मुकेश अंबानी की ललकार, 75 साल पुराने ब्रांड को दिया नया अवतार, मची हलचल

एजेंसी नई दिल्ली

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने 75 साल पुराने मशहूर फूड ब्रांड SIL को नए अंदाज और स्वाद के साथ बाजार में उतारा है। आरसीपीएल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी कंपनी है। इस लॉन्च के साथ रिलायंस ने नूडल्स, केचप और जैम जैसे उत्पादों को 5 रुपये, 1 रुपये और 22 रुपये जैसी किफायती कीमतों पर पेश किया है, जो ग्लोबल क्वालिटी का वादा करते हैं। यह कदम रिलायंस के पैकेज्ड फूड सेगमेंट में पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। इससे 'मैगी' और 'क्रिसान' जैसे ब्रांडों को सीधी टक्कर मिलने के आसार हैं। यह खबर खाने-पीने के शौकीनों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने 75 साल पुराने प्रतिष्ठित फूड ब्रांड SIL को एक नए रूप में बाजार में पेश किया है। इस लॉन्च के साथ रिलायंस ने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। कंपनी ने SIL को अपने प्रमुख फूड ब्रांड के तौर पर स्थापित किया



है। रिलायंस के अनुसार, SIL नूडल्स की एक नई सीरीज लेकर आ रहा है। इस सीरीज की शुरुआत 5 रुपये से होगी। इसमें मसाला, आटा विंद वेजीज, कोरियन के-फायर और चाउ-चाउ जैसे चार अलग-अलग फ्लेवर मिलेंगे। इसके अलावा, असली टमाटरों से बना SIL केचप भी बाजार में उतारा गया है। इस केचप में किसी भी तरह के कृत्रिम रंग या सिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 1 रुपये रखी गई है। साथ ही, आठ तरह के फलों से तैयार SIL मिक्सड फ्रूट जैम भी पेश किया गया है। यह जैम 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के पैक्स में उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत 22 रुपये होगी। कंपनी का दावा है कि इस जैम में सामान्य जैम की तुलना में

22% ज्यादा फलों का कंटेंट होगा। कंपनी ने क्या कहा? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एजीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने इस लॉन्च पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'SIL का रिलॉन्च RCPL की ग्रोथ जर्नी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पैकेज्ड फूड सेगमेंट में SIL के जरिए हम एक मजबूत और हर घर तक पहुंचने वाला फूड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। SIL विरासत, भारतीयता और इनोवेशन का ऐसा मेल है, जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, वैल्यू-ड्रिवन फूड प्रोडक्ट्स पेश करेगा।' कुल मिलाकर, SIL की यह वापसी उन ग्राहकों के लिए बहुत खास है जो पुराने, जाने-पहचाने स्वादों के साथ आधुनिक क्वालिटी और कम दाम चाहते हैं। 75 साल की पुरानी पहचान के साथ SIL अब एक बार फिर से भारतीय घरों की रसोई में अपनी खास जगह बनाने के लिए तैयार है। यह रिलायंस के लिए फूड सेक्टर में एक बड़ा कदम है, जो किफायती दामों पर अच्छी क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करता है। SIL के नए प्रोडक्ट्स के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

45 साल में पहली बार हुआ ऐसा, चांदी ने कच्चे तेल को पीछे छोड़ा, तीन साल पहले पांच गुना ऊपर था कूड

एजेंसी नई दिल्ली

चांदी की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। हाल में इसकी कीमत पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 65 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गई। दूसरी तरफ डब्ल्यूटीआई कूड 55.93 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट कूड 59.71 डॉलर प्रति बैरल पर है। 1980 के बाद यह पहला मौका है जब चांदी की कीमत कच्चे तेल से ऊपर गई है। 2022 के मध्य में डब्ल्यूटीआई कूड की कीमत चांदी से करीब 5.5 गुना ज्यादा थी। उसके बाद से चांदी की कीमत में 206 फीसदी तेजी आई है जबकि कच्चे तेल की कीमत में 44 फीसदी गिरावट आई है। डब्ल्यूटीआई कूड के लिए यह साल महामारी के बाद सबसे खराब साल होने जा रहा है जबकि चांदी के लिए यह 1979 के बाद सबसे बेहतर साल है। इस साल



चांदी की कीमत में 115 फीसदी तेजी आई है। इसकी वैल्यूएशन भी माइक्रोसॉफ्ट से ऊपर पहुंच चुकी है और यह दुनिया की पांचवीं सबसे वैल्यूएबल एसेट है। एमसीएक्स पर आज चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दिख रही है। 5 मार्च को डिलीवरी वाली चांदी शाम 6.00 बजे 423 रुपये यानी 0.21 की गिरावट के साथ

1,97,478 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। पिछले सत्र में यह 1,97,901 रुपये पर बंद हुई थी और आज 1,95,056 रुपये पर खुली। आज यह कारोबार के दौरान 1,94,260 रुपये तक नीचे और 1,97,708 रुपये तक हाई गई। जानकारों का कहना है कि इंडस्ट्रियल मांग के कारण चांदी की कीमत में तेजी आ रही है।



रुपये की गिरावट दोधारी तलवार... कहां फायदा, किसे है नुकसान

एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय रुपये के कमजोर होने से एक बात पर बहस फिर से छिड़ गई है। वह यह कि क्या कमजोर मुद्रा वास्तव में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की नई रिपोर्ट के अनुसार, करेंसी का कमजोर होना अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परिणाम देता है। कई बार यह व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने के बजाय बिगाड़ देता है। रिपोर्ट बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, मशीनरी और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्षेत्रों को कमजोर रुपये से निर्यात में कुछ फायदा होता तो है, लेकिन आयात पर

उनकी भारी निर्भरता के कारण यह लाभ काफी कम हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करेंसी के कमजोर होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, मशीनरी और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को फायदा होता है। लेकिन, आयात पर ज्यादा निर्भरता के कारण आयात की लागत बढ़ जाती है। इससे होने वाले फायदे खत्म हो जाते हैं और व्यापार घाटा बढ़ जाता है। मैनयुफैक्चरिंग में कच्चे माल के आयात की लागत लगभग एक तिहाई है। इनपुट लागत बढ़ने से निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और कुल आयात बिल बढ़ जाता है। इसके उलट रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और कृषि-आधारित निर्यात ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे रुपये के कमजोर होने से लगातार फायदा होता है।

आयात पर कम निर्भरता के कारण यह क्षेत्र न केवल अधिक निर्यात करता है, बल्कि व्यापार संतुलन में भी सुधार दिखाता है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि खाद्य और कृषि-आधारित निर्यात ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां मुद्रा का कमजोर होना निर्यात में बढ़ोतरी और व्यापार संतुलन में सुधार दोनों से जुड़ा हुआ है। कारण है कि इसमें आयात की लागत कम होती है। इस संरचनात्मक लाभ के कारण मुद्रा की कमजोरी सीधे तौर पर क्षेत्र के लिए बाहरी लाभ में बदल जाती है। यह निष्कर्ष श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जिन्हें अक्सर कमजोर मुद्रा से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद की जाती है।

संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मान्यता है कि दोनों हाथों से सिर खुजलाने की आदत अशुभ होती है। जिसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसे विष्णु पुराण में भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से जातक के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कारोबार में निणय लेने में बाधाओं और उलझनों का सामना कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन में समस्याएं आने की संभावना बढ़ सकती है।

लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। धनु राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और मनोरथ सिद्धि होंगे। वहीं, रात्रि में मंगलमय समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।

मकर राशि करियर राशिफल- राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में उदय है किन्तु चन्द्रमा एकादश भाव में राज्य विजय कारक है। आज सत्पुरुषों के मिलने से मन में प्रसन्नता होगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। इससे भूमि-जायदाद संबंधी विवाद का समाधान हो सकता है। सायंकाल के समय आपका स्वास्थ्य कुछ ढीला हो सकता है।

कुंभ राशि करियर राशिफल- आपकी राशि स्वामी शनि द्वितीय भाव कोष में मीन राशि में अपने घर संचार कर रहे हैं। कर्मफल की सिद्धि कारक है। कहीं से कमा कमाया धन मिलने का योग बन रहा है। किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद मिलने से उन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। बहुत समय से भाई बिन्दुओं से चला आ रहा विवाद सुलझ जाएगा।

मीन राशि करियर राशिफल- आपकी राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति राशि से पंचम सुख भाव में कर्क राशि का होकर विद्यमान है। चंद्रमा भी आज वृश्चिक राशि पर नवम का चल रहा है। फलस्वरूप आज पूरे दिन आय के नए स्रोत सामने आएंगे। विरोध पक्ष पराजित होगा। आपके भाग्य का सितारा फिर से चमकने लगेगा। व्यवसाय में अधिक धन लगाना लाभकारी रहेगा।

मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट और दोष-धर्म-धीरे कम होने लगते हैं। इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, फल प्रद, फूल और धूप-दीप अर्पित कर पूजा करने से विषय प्रेत प्राप्ति होता है। मान्यता है कि लगातार 11 प्रदोष व्रत रखने से सभी कष्ट, पाप और दुख दूर होते हैं और भगवान् शिव और माता पार्वती की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विवाह की इच्छा रखने वाली कन्याओं को इस दिन माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि



शासकीय महाविद्यालय में मनाया गया झंडा दिवस

बड़ी संख्या में महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे उपस्थित

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु सिंग उईके शासकीय महाविद्यालय सारनी द्वारा कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार विजय दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में मंगलवार को झंडा दिवस और विजय दिवस महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य प्रदीप पंद्राम द्वारा सरस्वती पूजन के साथ की गई। प्राचार्य द्वारा विजय दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला और डॉ. हरीश लोखंडे ने विजय दिवस पर विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी और नौसेना में अपनी सेवा देने का अवसर कैसे पाए इस के बारे में विस्तार पूर्वक छात्र छात्राओं को बताया। कार्यक्रम का मंच संचालन दिनकर लिखितकर द्वारा लिया गया। महाविद्यालय परिवार डॉ. गोलमाल आहके, डॉ. अंजना संजय, डॉ. दीपक मानकर, डॉ. दसरू यदुवंशी, ज्योति भावरसे, अर्चना महाले, अनुज हालदार, लक्ष्मी नागले, रीना उईके, निकिता सोनी, अनीता नागले, गंगा चौर, अनिल तुमडाम, प्रियंका दवडे, मोहन पवार एवं समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।



बैतूल में अंतरजातीय विवाह पर जाति पंचायत का दबाव

सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने के आरोप, 10 लोगों पर जांच शुरू



दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल जिले के शाहपुर तहसील के भयावाड़ी गांव में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों और उनके परिवारों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। जातिगत पंचायतों पर सामाजिक बहिष्कार, अपमान और जबरन उगाही का आरोप है। आधा दर्जन से अधिक परिवारों ने इस संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। एक पीड़िता ने बताया कि छह वर्ष पूर्व प्रेम विवाह करने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उसे 'नीच जाति' कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि गांव के प्रभावशाली लोगों ने उसे और उसके परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया है। उन्हें गांव के सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल नहीं किया जाता। रिश्तेदारों को भी उनके घर न बुलाने की हिदायत दी गई है। पीड़िता ने कहा, 'मुझे और मेरे पति को दलित कहकर बार-बार अपमानित किया गया। उसी डर से मैं अब गांव छोड़कर बाहर रह रही हूँ।' यह केवल एक जोड़े

का मामला नहीं है। गांव के अन्य प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों के परिजन भी सामने आए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जाति पंचायतों द्वारा उन पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि बेटे का अंतरजातीय विवाह करने पर पंचायत ने 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे मजबूरी में चुकाना पड़ा। शिकायतों में यह भी बताया गया है कि पंचायतें 'जात मिलाने' और 'सामाजिक मर्यादा' के नाम पर प्रभावित परिवारों से जबरन रकम वसूल रही हैं। जो परिवार इन फैसलों का विरोध करते हैं, उन्हें गांव की सभाओं और सामाजिक आयोजनों से बाहर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर एएसपी कमला जोशी ने बताया कि भयावाड़ी गांव में प्रेम विवाह करने वालों के विरोध और सामाजिक बहिष्कार की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा, 'करीब 10 लोगों के खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करवाई जा रही है।' पीड़ितों ने प्रशासन से एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ताप्ती नदी प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी

ताप्ती विकास प्राधिकरण समिति ने कलेक्टर से की शिकायत, जनसुनवाई में दिया आवेदन

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल के मुलताई स्थित मां ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर का गंभीर मामला सामने आया है। ताप्ती विकास प्राधिकरण समिति ने कलेक्टर जनसुनवाई में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ताप्ती विकास प्राधिकरण समिति मुलताई की ओर से दीपक कालभोर ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान हिन्दू सेना के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आवेदन में बताया गया कि वर्ष 1917-18 के खसरा रिकॉर्ड में खसरा नंबर 242 (रकबा 0.58 हेक्टेयर) "ताप्ती नदी पानी के नीचे" दर्ज था। समिति के अनुसार 1954-55 के अधिकार अभिलेख में इसी खसरा नंबर को 242/1 (0.38), 242/2 (0.10) और 242/3 (0.10) में विभाजित कर दिया गया। इससे मां ताप्ती नदी के प्रवाह क्षेत्र का बंटवारा हो गया। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 1972-73 के रिकॉर्ड में खसरा नंबर



240 और 242/3 को जोड़कर नया खसरा नंबर 560 बना दिया गया। इससे नदी के प्रवाह क्षेत्र की जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज हो गई। शिकायत में कहा गया है कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होने से मां ताप्ती कुंड का जल बहाव बंद हो गया है।

बारिश के दौरान कुंड का पानी ऊपर से बहकर आसपास के प्राचीन मंदिरों और रिहायशी इलाकों में भर जाता है। इससे ताप्ती तालाब में दरारें पड़ चुकी हैं और अधिक दबाव के कारण तालाब टूटने व जनहानि की आशंका बनी हुई है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले

की निष्पक्ष जांच कराई जाए, मां ताप्ती नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पुनः बहाल किया जाए और अवैध रूप से दर्ज की गई भूमि को फिर से नदी के नाम दर्ज किया जाए, ताकि धार्मिक धरोहरों और स्थानीय आबादी को संभावित आपदा से बचाया जा सके।

बैतूल में ग्रामीण बिजली और पानी की कमी से परेशान

रामपुर व पिपरिया गांव में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा प्रभावित

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल जिले में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। ग्राम पंचायत रामपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोघरा के निवासियों ने बताया कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी उनका गांव बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही, रात में अंधेरे के कारण सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के खतरे से भी लोग परेशान हैं। समस्त ग्रामीणों की ओर से दिए गए आवेदन में प्रशासन से आगामी चुनाव से पहले इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। वहीं, ग्राम पंचायत पिपरिया (गुरुवा) के मोहला



सरपंच ढाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पेयजल संकट की समस्या उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि पांच वर्ष पहले नल-जल योजना तो शुरू हुई थी, लेकिन आज तक पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे गांव के लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं।



ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल पानी और बिजली की व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास योजनाओं का लाभ अब तक उनके गांव तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे गांव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

16 दिनों में ग्यारह हजार क्विंटल धान की खरीदी

182 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेची उपज भुगतान एक सप्ताह में

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल पर जारी धान खरीदी के तहत कृषि साख सेवा सहकारी समिति रानीपुर ने 16 दिनों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समिति के माध्यम से रानीपुर क्षेत्र के लगभग 182 किसानों ने गायत्री वेयरहाउस रानीपुर में 11 हजार क्विंटल धान का विक्रय किया है। अभी भी 918 किसानों से धान खरीदी शेष है, जिसके लिए प्रक्रिया निरंतर जारी है। किसानों के लिए बेहतर इंतजाम समिति के प्रबंधक परशराम वर्मा ने बताया कि खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वेयरहाउस परिसर में पीने के पानी के कैंप लगाए गए हैं तथा ठंड से बचाव के लिए अलाना की व्यवस्था

भी समिति द्वारा की गई है। इससे दूर-दराज से आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। **भुगतान और स्लॉट बुकिंग में नहीं परेशानी** : खरीदी केंद्र पर मौजूद किसान शिवराज झल्लारे, पंजाब मालिया, अशोक पटेल, राजकुमार पटेल, दिनेश पटेल सहित अन्य किसानों ने बताया कि धान बेचने के बाद एक सप्ताह के भीतर भुगतान प्राप्त हो रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि स्लॉट बुकिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है और यदि कोई समस्या होती है तो समिति प्रबंधक द्वारा तत्काल प्रभाव के साथ मार्गदर्शन कर समाधान कर दिया जाता है। कुल मिलाकर रानीपुर खरीदी केंद्र पर व्यवस्थाएं सुचारु रहने से किसानों में संतोष दिखाई दे रहा है।



स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मधुवर मोहन द्विवेदी द्वारा इंविपेंडेंट प्रेस, 11 प्रेस काम्पलेक्स, एमपी नगर जोन-1 भोपाल 462023 म.प्र. से मुद्रित एवं 201 ब्लाक ई, सागर प्रीमियम टावर जेके हॉस्पिटल, कोलार रोड, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा) संपादक- सुनील यादव, समाचार संपादक- राहुल कौशिक। फोन नं. 0755-4262585-9425006706, मो. नंबर 9826697203, 9926288166, RNI.No. MPHIN/2020/78949

